प्रभाकर राव एन. मवाल

बनाम

आंध्र प्रदेश राज्य

9 अप्रैल, 1965

[के. सुब्बा राव, के. एन. वांचू, एम. हिदायतुल्ला, जे. सी. शाह और एस. एम. सिकरी, जे. जे.]

मद्रास कष्टकारी मुकदमेबाजी (रोकथाम) अधिनियम, (1949 के अधिनियम 8) की धारा 2(1) और राज्य पुनर्गठन अधिनियम (1956 का 37) की धारा 65, 119 और 121- मद्रास अधिनियम की आंध्र प्रदेश राज्य के तेलंगाना क्षेत्र में प्रयोज्यता।

मद्रास कष्टकारी मुकदमे की (रोकथाम) अधिनियम 1949 के धारा 2(1) के तहत मद्रास उच्च न्यायालय यह आदेश किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध जारी करने में सक्षम था कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध उसके द्वारा किसी भी न्यायालय में (i) प्रेसीडेंसी-शहर में उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना, और (ii) कहीं और कोई कार्यवाही जिला और सेशन न्यायाधीश की अनुमति के बिना शुरू नहीं की जाएगी। आंध्र प्रदेश के महाधिवक्ता के आवेदन पर आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि हैदराबाद शहर में उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना, सिकंदराबाद शहर में मुख्य शहर सिविल न्यायाधीश की अनुमति के बिना और अन्य जगहों पर,

संबंधित जिला और सत्र न्यायाधीश की अनुमति के बिना अपीलार्थी द्वारा कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जानी चाहिए।

इस न्यायालय में अपनी अपील में, अपीलार्थी ने तर्क दिया किः (i) उच्च न्यायालय को इसके तहत कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं क्योंकि अधिनियम के प्रावधानों को राज्य के तेलंगाना क्षेत्र में विस्तारित नहीं किया गया था, जो पूर्व हैदराबाद राज्य का हिस्सा था; और (ii) अधिनियम असंवैधानिक था क्योंकि यह कुछ नागरिकों को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अनुतोष प्राप्त करने से रोकता था, जिसका कानून के शासन द्वारा शासित राज्य में हर कोई हकदार है।

अभिनिर्धारित: (i) (के. सुब्बा राव, के. एन. वांचू, एम. हिदायतुल्ला और एस. एम. सीकरी, जे. जे.) उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटि की कि अधिनियम ने परेशान करने वाले मुकदमेबाजी में अभ्यस्त व्यक्तियों के प्रक्रियात्मक प्रतिबंध के लिए एक प्रक्रियात्मक क्षेत्राधिकार का निर्माण किया है, मद्रास के पूर्व उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र जो मद्रास और आंध्र प्रदेश के दो उच्च न्यायालयों में विभाजित होने पर दोनों उच्च न्यायालयों में अंतर्निहित बने रह आंध्र प्रदेश का न्यायालय उन आर्काओं के प्रयोजनों के लिए भी अंतर्निहित बने रहा था यहां तक कि उन क्षेत्रों के प्रयोजनों के लिए भी जिनके लिए अधिनियम का विस्तार नहीं किया गया था, [752 डी-एफ]

यह अधिनियम मद्रास प्रांतीय विधानमंडल द्वारा पारित किया गया था, और मद्रास उच्च न्यायालय को तंग करने वाले मुकदमों में लिप्त स्थायी वादियों से निपटने के लिए अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया। यह मद्रास उच्च न्यायालय का अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र नहीं था। आंध्र राज्य अधिनियम, 1953 की धारा 30, 53 के अनुसार, आंध्र राज्य और आंध्र उच्च न्यायालय में पूर्व मद्रास उच्च न्यायालय के समान अधिकार क्षेत्र था। लेकिन यह पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत पूर्व हैदराबाद राज्य के तेलंगाना क्षेत्र जोड़कर गठित आंध्र प्रदेश राज्य में अप्रभावी है। धारा 65 राज्य पुनर्गठन अधिनियम स्थिति को नहीं बदलता है। [753 - एच]

सभी कानूनों का उद्देश्य क्षेत्रीय रूप से काम करना है और भारत में किसी प्रांतीय कानून को अतिरिक्त-क्षेत्रीय अधिकार नहीं है। मद्रास अधिनियमित कानून को अपने क्षेत्र में काम करना था और ऐसा मद्रास कष्टकारी मुकदमे की (रोकथाम) अधिनियम 1949 में कहा है। इसके ऑपरेटिव भाग में भी, अधिनियम के तहत आदेश मद्रास की प्रेसीडेंसी शहर और मद्रास की शेष प्रेसीडेंसी के बीच क्षेत्रीय भेद के साथ बनाया जाना था। अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय को एक विशेष प्रकार के वादी से निपटने के लिए, अधिकार क्षेत्र निहित किया था लेकिन अधिनियम ने उच्च न्यायालय को मामले क्षेत्रीय रूप से देखने के लिए अधिकार क्षेत्र प्रदान किया है और अगर नए क्षेत्रों में इसके द्वारा शासित किया जाना था तब इसे नए क्षेत्र में विस्तारित किया जाना था और इतने विस्तारित होने

तक, अधिनियम केवल पुराने क्षेत्र के भीतर ही काम कर सकता था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 119 के तहत समामेलित करने वाले राज्यों का सक्षम प्राधिकारी और सक्षम विधायी को छोड़कर कानून अन्य समामेलित करने वाले राज्य में विस्तार नहीं किया जाना है, आगे कानून को प्रत्येक राज्य के पुनर्गठन से ठीक पहले के क्षेत्रों तक ही सीमित माना जाएगा। चूंकि इस अधिनियम का विस्तार तेलंगाना क्षेत्र तक नहीं किया गया है उस क्षेत्र में अधिनियम की धारा 119 के अनुप्रयोग को असंभव बना दिया गया है और इसे न्यायिक निर्माण द्वारा विस्तारित नहीं किया जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं, न्यायालय के पास धारा 121 राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम के तहत कानून को इस तरह से अनुकूलित करके नवगठित राज्य में उनके प्रयोग का आसान अर्थ निकालने के लिए शक्ति है, लेकिन शक्ति अनुकूलन के लिए है विधान के लिए नहीं। क्षेत्रों में वृद्धि जिसमें अधिनियम लागू होना है उस विधान पर निर्भर करता है जैसे कि धारा 119 में विचार किया गया है। [753 एफ-एच; 754 ए-सी]

इसके अतिरिक्त, आंध्र राज्य में कोई प्रेसीडेंसी शहर नहीं है, इसिलिये अधिनियम की धारा 2(1)(i) आंध्र राज्य में लागू नहीं होता है। उपधारा में प्रेसीडेंसी शहर का उल्लेख उच्च न्यायालय के स्थान को इंगित करने की दृष्टि से नहीं, बल्कि इसलिए कि मद्रास उच्च न्यायालय, प्रेसीडेंसी शहर में मूल अधिकार क्षेत्र रखता था। इसलिए, हैदराबाद शहर और आंध्र प्रदेश के अन्य हिस्सों के बीच उच्च न्यायालय द्वारा किया गया अंतर कृत्रिम अंतर

था ऐसा भेद उच्च न्यायालय द्वारा नहीं किया जाना चाहिए था। धारा 2 (1)(ii) भी लागू नहीं होती है क्योंकि, यह तर्क कि पूरे राज्य को उस उपधारा द्वारा शासित माना जा सकता है विचित्र परिणाम की ओर ले जाता है कि जिला और सत्र न्यायाधीश यह तय करें कि क्या किसी विशेष वादी को उच्च न्यायालय अपील, पुनरीक्षण या मूल कार्यवाही में आगे बढ़ने की अनुमति दी जानी चाहिए। [754 ई-एच]

न्यायाधिपति शाह के अनुसार, (असहमति): संसद द्वारा राज्य अधिनियम के अंतर्गत आंध्र राज्य के उच्च न्यायालय को उन सभी अधिकारिता लागू करने का अधिकार दिया जो मद्रास उच्च न्यायालय के पास आंध्र राज्य के क्षेत्रों में थी और उसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 65(1) ने आंध्र प्रदेश के पूरे क्षेत्र पर उस अधिकार का प्रयोग बढ़ाया। इस तर्क को स्वीकार करना असंभव होगा कि मद्रास कष्टकारी मुकदमेबाजी (रोकथाम) अधिनियम, द्वारा प्रदत्त अधिकारिता के संबंध में, आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय आदेश पारित करने में असमर्थ था जो उसने अपीलार्थी के खिलाफ या था। [759 ए-सी]

आंध्र उच्च न्यायालय मद्रास उच्च न्यायालय का उत्तराधिकारी था। न्यायालय ने सभी शक्तियों का प्रयोग किया और उसी कानून को प्रशासित किया जिसका प्रयोग आंध्र राज्य में शामिल क्षेत्रों में किया गया था। संसद ने आंध्र राज्य अधिनियम, की धारा 55 मे स्पष्ट रूप से प्रावधान प्रदान

किया था कि कोई न्यायालय किसी ऐसे कानून का अर्थ लगा सकता है जिसे उसे लागू करना है, ऐसे परिवर्तनों के साथ जो उस मुख्य अर्थ को प्रभावित नहीं करे और जो न्यायालय के समक्ष मामले को अनुकूलित करने के लिए आवश्यक या उचित हो, "प्रेसीडेंसी टाउन" अभिव्यक्ति का अर्थ, पृथक आंध्र उच्च न्यायालय के संविधान के संदर्भ में, उस राज्य का शहर जिसमें उच्च न्यायालय स्थित था होना चाहिए। यदि यह मना जाता है कि उच्च न्यायालय आंध्र को रोकथाम अधिनियम के तहत, आदेश पारित करने का अधिकार था तो यह मानना मुश्किल होगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 119 आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में परेशान करने वाले वादी को कार्यवाही शुरू करने से रोकने की शक्ति के प्रयोग को प्रतिबंधित किया जाता है। राज्य पुनर्गठन की धारा 65 (1) अधिनियम जिसे धारा 119 के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए, जो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को अधिकृत करता है की वह सभी प्रकार के क्षेत्राधिकार का प्रयोग करें, जो आंध्र उच्च न्यायालय मौजूदा राज्य हैदराबाद से आंध्र प्रदेश राज्य में हस्तांतरित सभी क्षेत्रों पर करता था। मद्रास कष्टकारी मुकदमेबाजी (रोकथाम) अधिनियम, के लिए यह आवश्यक नहीं है कि जिस व्यक्ति को प्रतिबंधित किया जाना है, वह न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर निवास करें या उसका अधिवास हो और न ही आदेश में कोई भी प्रत्यक्ष क्षेत्रीय संचालन पर विचार किया जाना है। व्यक्तिगत निर्देश ही प्रतिबंधित व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाता है। जब उच्च

न्यायालय आदेश सुनाता है तो उचित मामले केवल उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा इसे हटाया जा सकता है, जहां कार्यवाही शहर की किसी भी न्यायालय में शुरू की जानी है जहां उच्च न्यायालय स्थित है, और अन्यत्र जिला एवं सत्र न्यायालय के आदेश द्वारा इसे हटाया जा सकता है; और इसलिए, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के बीच अधिकार क्षेत्र का कोई टकराव नहीं है। [756 डी-एच]

((ii) (पूर्ण न्यायालय द्वारा): यह अधिनियम असंवैधानिक नहीं है।

मुकदमेबाज जिन्हें न्यायालय जाने से रोका जाता है ऐसे व्यक्ति हैं जो उचित मंजूरी के बिना आदतन परेशान करने वाली शिकायत दर्ज करते हैं। यहां तक कि वे न्यायालय में अपने वास्तविक और प्रामाणिक कार्यवाही के अधिकार के लिए जाने से भी वंचित नहीं हैं लेकिन अधिनियम केवल नियंत्रण बनाता है। अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक भलाई को बढ़ावा देना है, क्योंकि, यह नहीं हो सकता है किसी भी नागरिक को नियंत्रण के बिना परेशान करने वाला दावा लाने का अधिकार है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार/मूल क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. **900/1963**

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के सी.एम.पी. सं. 239/1960 के निर्णय और आदेश दिनांकित 21 अप्रैल 1961 से विशेष अनुमति द्वारा अपील।

के साथ

रिट याचिका सं. 146।/1961

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन के लिए याचिका।

और

सिविल विविध याचिका संख्या 186/ 1962

पंजीयक के दिनाक 21 नवंबर 1961 के याचिकाकर्ता का न्यायालय-शुल्क वापसी के लिए आवेदन को अस्वीकार करने के आदेश के खिलाफ अपील।

अपीलार्थी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित।

प्रतिवादी की ओर से (सी. ए. सं. 900/63 और रिट याचिका सं.146/1961) में के. आर. चौधरी और बी. आर. जी. के. आचार उपस्थित।

सुब्बा राव, वांचू, हिदायतुल्ला और सीकरी का निर्णय, जे.जे. हिदायतुल्लाह द्वारा दिया गया था, जे. शाह, जे. ने एक अलग राय दी।

हिदायतुल्ला, जे. 11 जनवरी, 1960 को महाधिवक्ता ने अपीलकर्ता प्रभाकर राव एच. मावले के खिलाफ धारा 2 कष्टकारी मुकदमेबाजी (रोकथाम) अधिनियम 1949 (1949 का मद्रास अधिनियम VIII) के तहत कार्रवाई के लिए आंध्र प्रदेश, हैदराबाद के उच्च न्यायालय में आवेदन

किया। इस आरोप पर कि मावले "आदतन" और बिना किसी उचित आधार के हैदराबाद और सिकंदराबाद शहरों के भीतर की अदालतों में और उच्च न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से मामलों में उपस्थित हो "परेशान करने वाली कार्यवाही" शुरू कर रहे थे। वह काफी मात्रा में मुकदमेबाजी के लिए जिम्मेदार था या, दूसरे शब्दों में, कि वह एक परेशान करने वाला और आदतन मुकदमा करने वाला व्यक्ति था। याचिका के समर्थन में अधिनियम के दंडात्मक प्रावधान के आह्वान के लिए महाधिवक्ता ने निम्नलिखित मामलों का उल्लेख किया:--

(1) सीआरपी संख्या 1765/58 में मावले ने निचली न्यायालय के फैसले का वर्णन इस प्रकार किया: " .....न्याय की भावना को झकझोर देने वाला, गंभीर अपमान कर्त्तव्य, कानून और प्राकृतिक न्याय के मौलिक सिद्धांतों का घोर दुरुपयोग, स्पष्ट त्रुटियों से भरा हुआ, अत्याचारी मनमाने कृत्यों के माध्यम से किए गए घोर स्पष्ट अन्याय को दर्शाता है।"

यह कहा गया कि मावले ने बचने के लिए अवमानना के लिए कार्यवाही में उच्च न्यायालय से माफी मांगी ।

(ii) उपरोक्त सिविल पुनरीक्षण याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने एक रिट याचिका संख्या 1369/18 दायर की और फिर सीसीसीए 42/59 अपील दायर की।'

(iii) उन्होंने एक इच्छित निष्पादन में कदम उठाए जाने से पहले उसके खिलाफ स्थगन याचिका दायर की और और जब याचिका खारिज कर दी गई तो उसने अपील सीएमए 86/59 दायर की और स्थगन प्राप्त कर लिया।

(iv) उन्होंने रिट याचिका 1369/58 को खारिज करने के खिलाफ अपील दायर की।

इस प्रकार कहा गया कि उन्होंने एक मुकदमे (ओएस 200/1958) में पांच उपचार मांगे थे।

(v) दिनाक 3-6-1959 को दायर एक अपील में उन्होंने 995 रुपये की अदालती फीस का भुगतान स्टांप उपलब्ध नहीं होने के कारण नहीं किया और उसने शेष राशि का भुगतान करने का वचन दिया, जिसे उसने नहीं चुकाया।

(vi) एसआर 38516 और एससीसीएमपी में मावले ने कहा कि चूंकि वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए थे-

"कानून के मामले में उनकी दलीलों को कोई महत्व दिए बिना, न्यायहित में, पेशेवर विशेषाधिकारों के विपरीत, इन दोनों अनुभवी अधिवक्ताओं (श्री ओवी सुब्बानायडू और श्री हरि नारायणलाल) द्वारा दावा किए गए, भले ही उन्होंने एक पक्ष की भूमिका निभाई थी, एकमात्र गवाह, झूठे हलफनामे की शपथ लेते हुए ..... "।

(vii) ओएस 109/1958 में डिक्री के खिलाफ एसआर 12409/59 में, एकमात्र प्रतिवादी, मावले ने अपनी पत्नी और बच्चों द्वारा कंगाल के रूप में अपील की, अपील के तहत निर्णयों को निजी तौर पर मुद्रित किया और उन्हें सच प्रमाणित किया। .

(viii) सीआरपी संख्या 1094/59 में अपने किरायेदार के खिलाफ खारिज किए गए वाद संख्या 198/2 में फैसले के खिलाफ उसने एक पुनरीक्षण याचिका दायर की जिसे प्रारंभिक तौर पर खारिज कर दिया गया।

(ix) सिटी सिविल कोर्ट, हैदराबाद के ओएस 1957 के 99/2 में आईए 230/58 के खिलाफ दायर सीआरपी नंबर 988/1959 को तत्काल खारिज कर दिया गया।

(x) उन्होंने एक लघु वाद के मुकदमे के खिलाफ सीआरपी की समीक्षा करने से इनकार करने वाले आदेश के खिलाफ एलपीए के रूप में एसआर 31845/59 दायर किया है और एक समीक्षा याचिका दायर करने में देरी को माफ करने से इनकार करने वाली याचिका में एक आदेश के खिलाफ एलपीए के रूप में एसआर संख्या 27605/59 दायर किया है।

(xi) एक लघु वाद के मुकदमे में एलआर याचिका में एक आदेश के खिलाफ सीआरपी 954/1959 दायर किया गया था, मूल रूप से एक अपील के रूप में दायर करने का प्रयास किया गया था, सीएमपी 5518 दायर किया गया और इस शर्त पर स्थगन आदेश दिया गया कि मावले को

डिक्रीटल राशि जमा करनी होगी। इसके बाद उन्होंने सीएमपी वापस ले लिया।

(xii) उच्च न्यायालय में कई आपराधिक मामले। सीआर 406/58 एवं सी.आर.एल. आरसी 506/59 में शिकायत।

(xiii) न्यायालय की कथित अवमानना के लिए प्रतिवादी के खिलाफ कार्रवाई के लिए सीएमपी 1858/57।

(xiv) एसआर नंबर 43198/59, एक एलपी अपील।

महाधिवक्ता ने दावा किया कि यद्यपि अधिनियम को पूर्व हैदराबाद राज्य के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र तक विस्तारित नहीं किया गया था, इसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के कारण वहां कानून रूप में लागू माना जाना चाहिए।

मावले को नोटिस पर सुना गया और, जैसा कि उनके जैसे वादी से उम्मीद की जाती थी, उन्होंने प्रत्येक आरोप से इनकार करते हुए और अपने आचरण की व्याख्या करते हुए जवाब में काफी लंबा बयान दिया। उन्होंने अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया क्योंकि इसके प्रावधानों को पूर्व हैदराबाद राज्य में शामिल क्षेत्र तक विस्तारित नहीं किया गया था। उन्होंने इस अधिनियम को अधिकार क्षेत्र से बाहर और असंवैधानिक बताते हुए इस आधार पर चुनौती दी कि यह नागरिकों के न्यायालय में शिकायत

निवारण के अधिकार को समाप्त करता है। उन्होंने कहा कि वह एक व्यवसायी और जमींदार थे और उनके पास हैदराबाद शहर और जिले और राज्य के अन्य शहरों में काफी संपत्ति थी। उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि अप्रिय अनुभव के कारण उन्हें वकीलों से अपना काम छीनना पड़ा और 1952 से उन्होंने अपने मामले स्वयं संचलित करना शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें अपने ग्राहकों/किरायेदारों आदि से कुछ लाख रुपये वसूलने थे और इसलिए बड़ी संख्या में मामले दर्ज करने पड़े। उन्होंने उन मामलों की व्याख्या करने का प्रयास किया जिनका उल्लेख महाधिवक्ता ने अपनी याचिका में किया था।

उच्च न्यायालय ने दिनांक 21 अप्रैल, 1961 के अपने फैसले में, जो अब अपील के अधीन है, माना कि अधिनियम संवैधानिक और अधिकारगत दोनों है, उच्च न्यायालय के पास आदेश देने का अधिकार क्षेत्र था और अधिनियम के तहत उक्त कार्रवाई की आवश्यकता थी। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि मावले द्वारा हैदराबाद शहर में उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना, सिकंदराबाद शहर में, मुख्य शहर सिविल न्यायाधीश की अनुमति के बिना और अन्यत्र संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के बिना अनुमति के कोई भी सिविल या आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जानी चाहिए। अधिनियम के अनुसार उच्च न्यायालय के आदेश की एक प्रति आंध्र प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी। मावले ने संविधान के अनुच्छेद 132, 133, या 134 के तहत एक प्रमाण पत्र मांगा, लेकिन प्रमाण पत्र को इस

आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि संविधान की व्याख्या के संदर्भ में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल नहीं था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने आवेदन किया और इस न्यायालय से विशेष अनुमति प्राप्त की और वर्तमान अपील दायर की।

जिस अधिनियम से हमारा सरोकार है, यद्यपि वह काफी हद तक 16 और 17 विक्ट अध्याय 30 (अब धारा 51 सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समेकन अधिनियम, 1925:15 और 16 जियो वी सी. 49 द्वारा प्रतिस्थापित है) की प्रतिलिपि है, शायद भारत में अपनी तरह का एकमात्र है। इसके प्रावधान अत्यंत संक्षिप्त हैं और उन्हें यहां पढ़ा जा सकता है:

"1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ।

(1) इस अधिनियम को कष्टकारी मुकदमेबाजी (रोकथाम) अधिनियम, 1949 कहा जा सकता है।

(2) पूरे मद्रास राज्य में इसका विस्तार होगा।

(3) यह तुरंत लागू होगा.

2. कष्टकर वादी को कार्यवाही शुरू करने के लिए न्यायालय की अनुमति आवश्यक है।

(1) यदि, महाधिवक्ता द्वारा किए गए आवेदन पर, उच्च न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि किसी भी व्यक्ति ने आदतन और बिना किसी उचित आधार के, किसी भी न्यायालय या अदालतों में नागरिक या

आपराधिक, कष्टप्रद कार्यवाही शुरू की है, तो उच्च न्यायालय, इसके बाद उस व्यक्ति को अपनी बात सुनाने का अवसर देकर, आदेश दे सकता है कि उसके द्वारा किसी भी न्यायालय में कोई दीवानी या आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी-

(i) प्रेसीडेंसी-नगर में, उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना; और

(ii) अन्यत्र, जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अनुमति के बिना।

(2) यदि उच्च न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ उपधारा (1) के तहत आवेदन किया गया है, वह गरीबी के कारण एक वकील को नियुक्त करने में असमर्थ है, तो उच्च न्यायालय उसके लिए उपस्थित होने के लिए एक वकील को नियुक्त कर सकता है।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजन के लिए 'वकील' का वही अर्थ है जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2, खंड (15) में है।

3. प्रथम दृष्टया आधार दर्शित होने पर ही अनुमति दी जाएगी। धारा 2 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुमति, किसी भी कार्यवाही के संबंध में तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि उच्च न्यायालय या, जैसा भी मामला हो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसी कार्यवाही के लिए प्रथम दृष्टया आधार है।

4. अनुमति के बिना शुरू की गई कार्यवाही को खारिज कर दिया जाएगा।किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा शुरू की गई कोई भी कार्यवाही, जिसके

खिलाफ धारा 2 की उपधारा (1) के तहत एक आदेश दिया गया है, उस उप-धारा में निर्दिष्ट अनुमति प्राप्त किए बिना खारिज कर दिया जाएगा।

बशर्ते कि यह धारा ऐसी अनुमति प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू की गई किसी भी कार्यवाही पर लागू नहीं होगी।

(5) आदेशों का प्रकाशन.

धारा 2 की उपधारा (1) के तहत किए गए प्रत्येक आदेश की एक प्रति को फोर्ट सेंट जॉर्ज राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।"

आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय ने माना है कि वह मद्रास के पूर्व उच्च न्यायालय के सभी क्षेत्राधिकार की अधिकारीता रखता है और इस प्रकार अधिनियम के प्रावधान उच्च न्यायालय में को अधिकारीता प्रदान करते हैं जिसे वह तेलंगाना क्षेत्र में प्रयोग करने में सक्षम है, भले ही अधिनियम राज्य उस क्षेत्र के इस हिस्से तक विस्तारित नहीं किया गया है। उच्च न्यायालय का भी मानना हैं कि अधिनियम पूरी तरह से वैध है।

इस अपील में उपरोक्त आधार पर आदेश पर सवाल उठाने के अलावा अपीलकर्ता का तर्क है कि मद्रास अधिनियम स्वयं अमान्य था क्योंकि यह भारत सरकार अधिनियम, 1935 की सूची II या III में किसी भी प्रविष्टि द्वारा कवर नहीं किया गया था और इसे गवर्नर-जनरल की सहमति नहीं मिली। यह तर्क निरर्थक है। अधिनियम को गवर्नर-जनरल की सहमति प्राप्त हो गई थी और कानून का विषय भारत सरकार अधिनियम, 1935 की सूची

II की प्रविष्टि 2 और सूची III की प्रविष्टि 2 और 4 में शामिल किया गया था। अपीलकर्ता का अगला तर्क है कि यह अधिनियम असंवैधानिक है क्योंकि यह कुछ नागरिकों को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अनुतोष प्राप्त करने से रोकता है जिसका कानून के शासन द्वारा शासित राज्य में हर कोई हकदार है। यह तर्क वास्तव में अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 14 का आह्वान करता है। अनुच्छेद 14 यह आह्वान करता है क्योंकि अपीलकर्ता के अनुसार अधिनियम, वादी और वादी के बीच अनुचित अंतर पैदा करना चाहता है। यह तर्क भी स्वीकार नहीं है क्योंकि जिन वादकारियों को उच्च न्यायालय आदि की मंजूरी के बिना न्यायालय में जाने से रोका जाना है, वे स्वयं एक वर्ग में हैं। उन्हें अधिनियम में ऐसे व्यक्तियों के रूप में वर्णित किया गया है जो 'आदतन' और 'उचित कारण के बिना' नागरिक या आपराधिक, कष्टदायक कार्रवाई दर्ज करते हैं। अधिनियम का उद्देश्य ऐसे व्यक्ति को न्यायालय में जाने के अधिकार से वंचित करना नहीं है। यह केवल एक नियंत्रण बनाता है ताकि न्यायालय विपरीत पक्ष को परेशान करने से पहले किसी भी दावे की प्रामाणिकता की जांच कर सके। इंग्लैंड में पारित एक समान अधिनियम, न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए कई मामलों में लागू किया गया है। अधिनियम का उद्देश्य जनता की भलाई को बढ़ावा देना है क्योंकि यह दावा नहीं किया जा सकता है कि विधायी या प्रशासनिक नियंत्रण के बिना कष्टप्रद कार्रवाई करना किसी भी नागरिक का अनुलंघनीय अधिकार है। यह अधिनियम सार्वजनिक

हित की रक्षा करता है और यह जो संयम पैदा करता है, वह सार्वजनिक भलाई को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। यह अधिनियम आदतन वादी घोषित व्यक्ति को वास्तविक और प्रामाणिक कार्रवाई करने से नहीं रोकता है। यह केवल परेशान करने वाले प्रयासों को कम करना चाहता है। न्यायालय के फैसले में, अधिनियम को असंवैधानिक या किसी भी अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला नहीं कहा जा सकता है।

अपीलकर्ता का अगला तर्क यह है कि अधिनियम को पूर्व राज्य हैदराबाद के क्षेत्र तक विस्तारित नहीं किया गया है और उच्च न्यायालय उस क्षेत्र में क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। यह विवाद बारीकी से विचार के योग्य है। उच्च न्यायालय ने राज्य और आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के विकास का इतिहास दिया है। यह सामान्य ज्ञान है कि मद्रास उच्च न्यायालय को लेटर्स पेटेंट 1865 के द्वारा स्थापित किया गया था और उस लेटर्स पेटेंट द्वारा प्रदत्त सभी मूल, अपीलीय और अन्य न्यायक्षेत्रों का प्रयोग किया गया था। मद्रास प्रांतीय विधानमंडल द्वारा 1949 में पारित अधिनियम, ने मद्रास उच्च न्यायालय को उन आदतन वादियों के मामलों से निपटने का अधिकार क्षेत्र प्रदान किया जो लगातार कष्टप्रद कार्रवाई दायर कर रहे थे और न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के दोषी थे। अधिनियम के आधार पर मद्रास उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एक अंतर्निहित क्षेत्राधिकार नहीं था, चाहे वह रिकॉर्ड न्यायालय के रूप में हो या अन्यथा।

जब 1953 में आंध्र राज्य अधिनियम 1953 द्वारा आंध्र राज्य का गठन किया गया, तो मद्रास उच्च न्यायालय का आंध्र राज्य के क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र समाप्त हो गया था। इस क्षेत्राधिकार का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त तिथि से आंध्र के उच्च न्यायालय द्वारा किया जाना था। आंध्र उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार मद्रास उच्च न्यायालय के समान ही होना था। आंध्र राज्य अधिनियम की धारा 30 इस प्रकार है:--

"30. आंध्र उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार

आंध्र उच्च न्यायालय के पास, आंध्र राज्य में फिलहाल शामिल किए गए क्षेत्रों के संबंध में, ऐसे सभी मूल, अपीलीय और अन्य क्षेत्राधिकार होंगे, जो निर्धारित दिन से पहले लागू कानून के तहत मद्रास में उच्च न्यायालय द्वारा उक्त क्षेत्रों या उसके किसी हिस्से के संबंध में क्षेत्राधिकार प्रयोग योग्य थे।" इस धारा के आधार पर नए उच्च न्यायालय के पास अपने क्षेत्र में मूल मद्रास उच्च न्यायालय के समान ही शक्तियाँ और अधिकार क्षेत्र थे। लेकिन आंध्र अधिनियम के धारा 53 दवारा कानूनों की क्षेत्रीय सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया था और मद्रास राज्य के सभी कानूनों के संदर्भों को आंध्र के नए राज्य में लागू करने के लिए नए राज्य को संदर्भित करने के लिए अनुकूलित किया जाना था। दूसरे शब्दों में, यह अधिनियम आंध्र राज्य में लागू अधिनियम बना रहा और आंध्र उच्च न्यायालय के पास पूर्व मद्रास उच्च न्यायालय के समान क्षेत्राधिकार था। अभी तक कोई

बाधा नहीं देखी गई है, लेकिन यह स्पष्ट है कि प्रेसीडेंसी टाउन में मद्रास उच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार का प्रयोग गुंटूर में नहीं किया जा सका और उच्च न्यायालय का पालन नहीं किया।

अगला परिवर्तन 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 द्वारा आया। उस अधिनियम द्वारा कुछ क्षेत्रों को आंध्र राज्य के साथ मिला दिया गया था और उन क्षेत्रों में प्रमुख था पूर्व हैदराबाद राज्य जिसे सुविधा के लिए यहां 'तेलंगाना क्षेत्र' के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। हैदराबाद शहर और सिकंदराबाद शहर उस क्षेत्र में हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 में विभिन्न क्षेत्रों में लागू कानूनों की क्षेत्रीय सीमा को सीमित करने के लिए एक विशेष प्रावधान था, जिन्हें मिलाकर आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 119 इस प्रकार प्रदान की गई है: -

"119. कानूनों की क्षेत्रीय सीमा

भाग II के प्रावधानों को उन क्षेत्रों में किसी भी बदलाव के लिए प्रभावी नहीं माना जाएगा, जहां नियत दिन से ठीक पहले लागू कोई भी कानून लागू होता है। और ऐसे किसी भी कानून में किसी मौजूदा का क्षेत्रीय संदर्भ राज्य को, जब तक कि सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है, नियत दिन से ठीक पहले उस राज्य के भीतर के क्षेत्रों के अर्थ के रूप में समझा जाएगा।"

अपीलकर्ता ने इस प्रावधान पर भरोसा करते हुए कहा कि अधिनियम के संचालन का क्षेत्र केवल आंध्र राज्य के पूर्व क्षेत्र हो सकते हैं और अधिनियम तेलंगाना क्षेत्र में शामिल क्षेत्र में लागू नहीं है। दूसरे पक्ष का तर्क है कि धारा 65 के आधार पर आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय आंध्र राज्य के उच्च न्यायालय के सभी क्षेत्राधिकार प्राप्त करता है और इसलिए यह अधिनियम द्वारा पूर्व आंध्र उच्च न्यायालय में निवेशित क्षेत्राधिकार प्राप्त करता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 65 इस प्रकार है:-

"65. आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय।

(1) नियत दिन से,--

(ए) मौजूदा आंध्र राज्य के उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार मौजूदा हैदराबाद राज्य से उस राज्य को हस्तांतरित सभी क्षेत्रों तक विस्तारित होगा;

(बी) उक्त उच्च न्यायालय को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के रूप में जाना जाएगा; और

सवाल यह उठता है कि क्या तेलंगाना क्षेत्र में अधिनियम को लागू करना अधिनियम की धारा 119 ने असंभव बना दिया गया है या निर्भर करता है उस अधिनियम के धारा 65 पर यदि जिस अधिनियम के तहत कार्रवाई की जानी है, उसे क्षेत्रीय रूप से संचालित कहा जा सकता है, तो यह स्पष्ट है कि जिस क्षेत्र में इसे लागू किया जाना था, वह न केवल राज्य

पुनर्गठन अधिनियम द्वारा बढ़ाया गया था, बल्कि धारा 119 के तहत भी पूर्व आंध्र राज्य के क्षेत्र तक सीमित करके कठोर रखा गया था। हालाँकि, यदि उस अधिनियम ने वादियों के एक विशेष वर्ग से निपटने के लिए उच्च न्यायालय में एक क्षेत्राधिकार बनाया, जो आदतन कष्टप्रद मुकदमे ला रहे थे, तो यह तर्क देना संभव हो सकता है कि क्षेत्राधिकार आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय में निहित है। उच्च न्यायालय ने इस मामले को बाद के दृष्टिकोण से देखा है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि धारा 65 इस मामले को नियंत्रित करती है ना की धारा 119।

उच्च न्यायालय का तर्क यह है कि अधिनियम मुकदमेबाजी को नियंत्रित करता है और उन व्यक्तियों के संबंध में एक नई प्रक्रिया बनाता है जो आदतन कष्टप्रद मुकदमेबाजी में शामिल होते हैं। अधिनियम ऐसे व्यक्तियों को प्रक्रियात्मक प्रतिबंध के तहत रखने का अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है और यह क्षेत्राधिकार पूर्व मद्रास उच्च न्यायालय में और बाद में मद्रास और आंध्र उच्च न्यायालयों में अलग-अलग विरासत में मिला और अब यह आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में विरासत में मिला है। उच्च न्यायालय की राय में, क्षेत्राधिकार का प्रयोग तेलंगाना क्षेत्र सहित आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के अधीन सभी क्षेत्रों में किया जा सकता है।

श्री के. आर. चौधरी इस तर्क को पूरक करते हुए बताते हैं कि मद्रास उच्च न्यायालय किसी के भी खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। वह व्यक्ति

जिसने अधिनियम के प्रावधानों को आकर्षित करने के तरीके से कार्य किया, भले ही वह व्यक्ति कहीं से भी आया हो। उनका तर्क है कि अधिनियम के दंडात्मक प्रावधानों के अधीन बंगाल या बॉम्बे के कष्टप्रद वादी भी आ सकते हैं है और कहा कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय उसी तरह से तेलंगाना क्षेत्र की अदालतों में अभ्यास और प्रक्रिया को नियंत्रित नहीं कर सकता है। उनके अनुसार, इस अधिनियम को तेलंगाना क्षेत्र तक विस्तारित माना जाना चाहिए क्योंकि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पास पूर्व मद्रास उच्च न्यायालय के सभी क्षेत्राधिकार हैं। यह उच्च न्यायालय में अपनी याचिका में महाधिवक्ता की मूल दलील भी थी, हालांकि स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालय ने इसे स्वीकार नहीं किया था।

हम श्री चौधरी के तर्क को स्वीकार नहीं करते हैं| मद्रास अधिनियम विधायिका द्वारा केवल मद्रास प्रेसीडेंसी पर लागू किया गया था। मान लीजिए कि इसे केवल एक जिले पर लागू किया गया था। क्या उच्च न्यायालय यह कह सकता था कि सीमित आवेदन के बावजूद, वह मद्रास प्रेसीडेंसी के अन्य जिलों में कार्रवाई करेगा? यदि यह मद्रास प्रेसीडेंसी में अधिनियम के आवेदन की क्षेत्रीय सीमाओं को नहीं बढ़ा सकता था, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 119 के प्रावधानों के मद्देनजर, स्थिति अब अलग नहीं है जिसमे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक सक्षम विधायी या अन्य सक्षम प्राधिकारी के अलावा विलय करने वाले राज्यों में

से किसी एक का कोई कानून अन्य एकीकृत राज्यों के क्षेत्र में विस्तारित नहीं किया जाएगा और इसके अलावा कानून को प्रतिबंधित पुनर्गठन से ठीक पहले प्रत्येक राज्य के भीतर के क्षेत्रों तक सीमित माना जाएगा| इस प्रकार न केवल प्रादेशिक क्षेत्र विस्तारित नहीं हुआ है बल्कि स्तम्भित किया गया है अब हम इस पर विचार कर सकते हैं कि क्या राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 65 से इस स्थिति पर कोई फर्क पड़ता है।

अधिनियम को कष्टप्रद मुकदमेबाजी को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था और इस उद्देश्य के लिए, एक नई प्रक्रिया बनाई गई थी जो उन व्यक्तियों पर लागू होती थी जो अदालतों में मुकदमेबाजी के रूप में न केवल अक्सर जाते थे बल्कि आदतन परेशान करने वाली भी होते थे। अधिनियम ने महाधिवक्ता को उच्च न्यायालय में आवेदन करने में सक्षम बनाया और उच्च न्यायालय इस बात से संतुष्ट होने पर कि कोई व्यक्ति इस तरीके से कार्य कर रहा है, आदेश दे सकता है कि प्रेसीडेंसी शहर में उस व्यक्ति द्वारा आगे कोई कार्यवाही उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना और अन्यत्र जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अनुमति के बिना दायर नहीं की जाएगी। इस अधिनियम का उद्देश्य पूरे मद्रास प्रेसीडेंसी में लागू करना था, जिसमें मद्रास प्रेसीडेंसी से अलग किया गया क्षेत्र जिसे 1953 में आंध्र राज्य में बनाया गया था भी शामिल था और जो अब 1956 के बाद आंध्र प्रदेश राज्य का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय रूप से कार्य करना था जैसा कि वास्तव में अधिनियम के लागू होने की सीमा से संबंधित खंड

स्वयं दर्शाता है। इसके संचालित हिस्से में भी आदेश प्रेसीडेंसी टाउन और मद्रास प्रेसीडेंसी के बाकी हिस्सों के बीच क्षेत्रीय अंतर के साथ बनाया जाना था। अधिनियम के तहत पारित किए जाने वाले आदेश में प्रेसीडेंसी टाउन में मुकदमा दायर करने से पहले उच्च न्यायालय की अनुमति और अन्यत्र जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अनुमति पर विचार किया गया था। यह स्पष्ट है कि अपनी शर्तों के अनुसार यह अधिनियम आंध्र प्रदेश राज्य में धारा 2(1)(i) में उल्लिखित प्रेसीडेंसी टाउन तक लागू नहीं हो सकता है। वह प्रेसीडेंसी टाउन मद्रास का शहर था और इसलिए अधिनियम की धारा 2(1)(i) आंध्र प्रदेश में लागू नहीं हो सकती, क्योंकि आंध्र प्रदेश में कोई प्रेसीडेंसी टाउन नहीं है जिससे धारा 2(1)(i) जुड़ती हो। हैदराबाद शहर और आंध्र प्रदेश राज्य के अन्य हिस्सों के बीच अंतर को उच्च न्यायालय द्वारा कृत्रिम रूप से हैदराबाद शहर के संबंध में आदेश देकर अस्तित्व में लाया गया है जैसे कि यह एक प्रेसीडेंसी शहर था। यह कानून शुद्ध और सरल है और इसे उच्च न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 2(1)(i) अब उचित संशोधन के बिना लागू नहीं हो सकती। हालाँकि, यह तर्क दिया जा सकता है कि धारा 2(1)(ii) लागू हो सकती है और पूरे नए आंध्र प्रदेश राज्य को उप-खंड (ii) द्वारा शासित माना जा सकता है। हालाँकि, जिला एवं सत्र न्यायाधीश से यह निर्णय लेना कुछ अजीब होगा कि किसी विशेष वादी को अपील, पुनरीक्षण या मूल कार्यवाही

में उच्च न्यायालय में जाने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। यह अधिनियम आंध्र प्रदेश राज्य में पर्याप्त संशोधनों के बिना अव्यवहारिक है।

जैसा कि उच्च न्यायालय ने तर्क दिया है, यह केवल प्रक्रियात्मक क्षेत्राधिकार का प्रश्न नहीं है । इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिनियम, जैसा कि यह था, एक विशेष प्रकार के मुकदमेबाजी से निपटने के लिए उच्च न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है, लेकिन अधिनियम ने उच्च न्यायालय को मामले को क्षेत्रीय रूप से निपटाने के लिए बनाया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्षेत्र बदल गया है, इसलिए सवाल उठता है कि क्या उच्च न्यायालय का पुराना क्षेत्राधिकार अब नए क्षेत्र में अधिकार ले सकता है। सभी कानूनों का उद्देश्य क्षेत्रीय रूप से कार्य करना है और भारत में किसी भी प्रांतीय विधानमंडल के पास राज्यक्षेत्रातीत क्षेत्राधिकार नहीं है। मद्रास विधानमंडल ने जो अधिनियम बनाया था, उसे अपने क्षेत्र में संचालित करना था और उसने अधिनियम में ऐसा कहा था। यदि नए क्षेत्रों को अधिनियम द्वारा शासित किया जाना है तो इसे नए क्षेत्रों तक विस्तारित किया जाना चाहिए और जब तक इसका विस्तार नहीं किया जाता तब तक अधिनियम केवल पुराने क्षेत्रों के भीतर ही संचालित हो सकता है और यह राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 119 का स्पष्ट परिणाम है|

इस प्रकार यह मानने की राह में कि यह अधिनियम नए राज्य आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में लागू है दो कठिनाइयां हैं। आरंभ करने के लिए इसे तेलंगाना क्षेत्र के रूप में जाने जाने वाले क्षेत्र तक विस्तारित नहीं किया गया है और, विस्तारित होने तक, राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 119 स्पष्ट रूप से न्यायिक निर्माण द्वारा तेलंगाना क्षेत्र के विस्तार पर रोक लगाता है। दूसरे, नए राज्य आंध्र प्रदेश में कोई प्रेसीडेंसी टाउन नहीं है | धारा2(1)(i) को अब नए आंध्र प्रदेश राज्य पर तब तक लागू नहीं किया जा सकता, जब तक कि इसके स्थान पर विधानमंडल द्वारा कोई अन्य शहर स्थापित नहीं कर दिया जाता। धारा 2(1)(i) में प्रेसीडेंसी टाउन का उल्लेख उच्च न्यायालय की सीट को इंगित करने की दृष्टि से नहीं था, बल्कि इसलिए बनाया गया था क्योंकि उच्च न्यायालय के पास उस क्षेत्र में मूल क्षेत्राधिकार था। बेशक, 'प्रेसीडेंसी टाउन' शब्द को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की सीट हैदराबाद को पढ़ने के लिए संशोधित किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं कि न्यायालय के पास राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 121 में कानूनों को इस तरह से अनुकूलित करके उन्हें परिभाषित करने की शक्ति है ताकि नवगठित राज्य में उनके लागू होने को सुविधाजनक बनाया जा सके, लेकिन जो शक्ति प्रयोग योग्य है वह केवल सरल अनुकूलन की शक्ति है और विधान मंडल की शक्ति नहीं है। जिन क्षेत्रों में कोई अधिनियम लागू होना है उनमें क्षेत्र की वृद्धि कानून पर निर्भर है जैसे कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा

119 द्वारा विचार किया गया है। उच्च न्यायालय ने जो किया है वह अनुकूलन से कहीं अधिक है। इसने न केवल प्रेसीडेंसी शहर के स्थान पर हैदराबाद शहर को प्रतिस्थापित किया है, बल्कि इसने राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 119 की मंशा के विपरीत कानून को तेलंगाना अदालतों पर भी लागू कर दिया है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 119 पूर्व में उच्च न्यायालय की सीट अलग थी और अधिनियम को उसी तर्क पर वहां लागू किया जाना चाहिए, ताकि 'प्रेसीडेंसी टाउन' शब्द पहले गुंटूर पढ़ा जाए और अब वे हैदराबाद पढ़ें। हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने यह मानने में गलती की थी कि अधिनियम ने केवल मद्रास उच्च न्यायालय में एक प्रक्रियात्मक क्षेत्राधिकार बनाया है, जो दो उच्च न्यायालयों में विभाजित होने पर, दोनों उच्च न्यायालयों में निहित है और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में उन क्षेत्रों के प्रयोजनों के लिए भी निहित है जहां अधिनियम का विस्तार नहीं किया गया है। इस मामले को देखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश बरकरार नहीं रखा जा सकता है और इसे अपास्त किया जाना चाहिए।

हम गुणों में नहीं गए हैं और मावले के खिलाफ उचित कार्रवाई के बारे में बहुत कुछ है। उन्होंने दर्जनों मामले दायर किए हैं और एक ही मामले पर बार-बार याचिकाओं के जरिए अदालतों में मुकदमेबाजी की बाढ़ ला दी है। जैसा कि हमने पाया कि उसके खिलाफ अधिनियम उपलब्ध नहीं है, हम और कुछ नहीं कहते हैं। हम रिकॉर्ड पर रख सकते हैं कि मावले ने

हमारे सामने अपनी मुकदमेबाजी में संयमित रहने की इच्छा व्यक्त की थी और हमें उम्मीद है कि वह अब अपने पिछले आचरण के लिए सुधार करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि वह भविष्य में उचित व्यवहार करेंगे।'

अपील की अनुमति है लेकिन मामले की परिस्थितियों में हम कॉस्ट के बारे में कोई आदेश नहीं देते हैं।

न्यायाधिपति शाह, मद्रास के प्रांतीय विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए 1949 का कष्टप्रद मुकदमेबाजी (रोकथाम) अधिनियम 8 अधिनियमित किया, अधिनियम के भौतिक प्रावधान हैं: -

"2. (1) यदि, महाधिवक्ता द्वारा किए गए आवेदन पर, उच्च न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि किसी भी व्यक्ति ने आदतन और बिना किसी उचित आधार के, किसी भी न्यायालय या अदालतों में सिविल या आपराधिक, कष्टप्रद कार्यवाही शुरू की है, तो उच्च न्यायालय उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के बाद, आदेश दें कि उसके द्वारा किसी भी न्यायालय में कोई भी कार्यवाही, नागरिक या आपराधिक, शुरू नहीं की जाएगी-

(i) प्रेसीडेंसी-नगर में, उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना; और

(ii) कहीं और, जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अनुमति के बिना।

(2)* *

*3. धारा 2 उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अनुमति किसी भी कार्यवाही के संबंध में तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि उच्च न्यायालय या, जैसा भी मामला हो, जिला और सत्र न्यायाधीश संतुष्ट न हो जाए कि ऐसी कार्यवाही के लिए प्रथम दृष्टया आधार है।

4. किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा शुरू की गई कोई भी कार्यवाही, जिसके खिलाफ धारा 2, उपधारा (1) के तहत आदेश दिया गया है, उस उपधारा में निर्दिष्ट अनुमति प्राप्त किए बिना खारिज कर दी जाएगी:

बशर्ते कि यह धारा ऐसी अनुमति प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू की गई किसी भी कार्यवाही पर लागू नहीं होगी।

5. धारा 2 उपधारा (1) के तहत किए गए प्रत्येक आदेश की एक प्रति फोर्ट सेंट जॉर्ज गजट में प्रकाशित की जाएगी।

इस अधिनियम द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय को कष्टकारी वादियों पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्रदान की गई। ऐसा प्रतीत होता है कि इस कानून का सिद्धांत ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित क़ानून 16 और 17 विक्ट अध्याय 30 से उधार लिया गया था। संविधान के अनुच्छेद 225, संविधान के प्रावधानों और उपयुक्त विधानमंडल के किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन मद्रास उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार वही रहेगा जो संविधान के प्रारंभ होने से ठीक पहले था। 14 सितंबर 1953 को आंध्र राज्य अधिनियम 30/1953 द्वारा आंध्र राज्य को मद्रास राज्य के क्षेत्रों से अलग कर दिया

गया था। उस अधिनियम की धारा 28 में प्रावधान था: "(1) जनवरी, 1956 के 1 दिन से, या ऐसी पहले की तारीख जो उप-धारा (2) के तहत नियुक्त की जा सकती है, आंध्र राज्य के लिए एक अलग उच्च न्यायालय होगा।"

आंध्र का उच्च न्यायालय जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अधिसूचना द्वारा किया गया था। धारा 30 के अधीन आंध्र राज्य में शामिल क्षेत्रों के संबंध में, निर्धारित दिन से ठीक पहले लागू कानून के तहत ऐसे सभी मूल, अपीलीय और अन्य क्षेत्राधिकार, मद्रास में उच्च न्यायालय द्वारा क्षेत्रों या उसके किसी भी हिस्से के संबंध में प्रयोग किए जा सकते थे। इसलिए आंध्र उच्च न्यायालय मद्रास उच्च न्यायालय का उत्तराधिकारी था और सभी शक्तियों का प्रयोग करता था और वही कानून प्रशासित करता था जो मद्रास उच्च न्यायालय आंध्र राज्य में शामिल क्षेत्रों में प्रयोग करता था। 1949 के अधिनियम 8 की धारा 2(1) के अनुसार मद्रास उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति के विरुद्ध आदेश जारी करने में सक्षम था कि न्यायालय में कोई भी कार्यवाही, सिविल या आपराधिक, (i) प्रेसीडेंसी टाउन में उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना (ii) अन्यत्र, जिला और सत्र न्यायाधीश की अनुमति के बिना; शुरू नहीं की जाएगी। और यह शक्ति, 1953 के अधिनियम की धारा 30 के तहत आंध्र उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग योग्य बन गई। सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की (धारा 3(44)) में अभिव्यक्ति "प्रेसीडेंसी-टाउन" का अर्थ है की कलकत्ता, मद्रास या बॉम्बे

उच्च न्यायालय के सामान्य मूल क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाएँ, यथास्थिति और 1953 के अधिनियम की धारा 30 द्वारा गठित आंध्र राज्य के क्षेत्र के भीतर कोई प्रेसीडेंसी-नगर नहीं था। हालाँकि, वर्तमान प्रकृति की विसंगतियों को पूरा करने की दृष्टि से विधायिका ने धारा 55 के अधीन कहा है कि "इसके बावजूद कि धारा 54 के तहत कोई प्रावधान या अपर्याप्त प्रावधान नहीं किया गया था, नियत दिन से पहले बनाए गए कानून के अनुकूलन के लिए, आंध्र राज्य के संबंध में इसके आवेदन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से, किसी भी न्यायालय को ऐसे कानून को लागू करने की आवश्यकता या अधिकार है। * * कानून को ऐसे परिवर्तनों के साथ परिभाषित करें जो उसके सार को प्रभावित न करें जो न्यायालय के समक्ष मामले के अनुसार उसे अनुकूलित करने के लिए आवश्यक या उचित हो* *।" आंध्र राज्य के गठन के बाद पृथक आंध्र उच्च न्यायालय के गठन के संदर्भ में अभिव्यक्ति "प्रेसीडेंसी टाउन" का, मतलब उस राज्य की राजधानी है जिसमें उच्च न्यायालय स्थित था। इस तरह का अनुकूलन अधिनियम के सार को प्रभावित नहीं करता है, और यह बदली हुई परिस्थितियों में इसके अनुप्रयोग की सुविधा प्रदान करेगा ।

नए आंध्र प्रदेश राज्य का गठन राज्य पुनर्गठन 1956 के 37 अधिनियम, के तहत धारा 3 द्वारा आंध्र के पुराने राज्य के क्षेत्र में कुछ निर्दिष्ट क्षेत्रों को शामिल करके किया गया था। धारा 65(1)(ए) द्वारा नियत दिन से अर्थात 1 नवंबर, 1956 को मौजूदा आंध्र राज्य के उच्च न्यायालय

के अधिकार क्षेत्र को मौजूदा हैदराबाद राज्य से उस राज्य को हस्तांतरित सभी क्षेत्रों तक विस्तारित करने की घोषणा की गई थी, उच्च न्यायालय को आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के रूप जाना जाता था, और उच्च न्यायालय की मुख्य सीट हैदराबाद में होनी थी। आंध्र के उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार धारा 65(1)(ए) में किए गए स्पष्ट प्रावधान द्वारा मौजूदा हैदराबाद राज्य से उस राज्य को हस्तांतरित पूरे क्षेत्र पर लागू होना था। मेरे निर्णय में, विधायिका द्वारा इस्तेमाल की गई पदावली, आंध्र प्रदेश के नए उच्च न्यायालय को उन सभी क्षेत्राधिकारों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करती है, जिनका प्रयोग आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय नियत दिन से पहले करता था। आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय ने 21 अप्रैल, 1961 को अपीलकर्ता के खिलाफ एक आदेश दिया कि अपीलकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना हैदराबाद शहर में कोई भी नागरिक या आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी; सिकंदराबाद शहर में मुख्य नगर सिविल न्यायाधीश की अनुमति के बिना ; और अन्यत्र संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अनुमति के बिना। यह स्पष्ट रूप से एक व्यक्तिगत निर्देश था 'जिसने अपीलकर्ता पर प्रतिबंध लगाए। धारा 2 के तहत प्रतिबंध लगाने की शक्ति, केवल उच्च न्यायालय में निहित है: विशिष्ट मामलों में प्रतिबंध हटाने की शक्ति उच्च न्यायालय, या जिला और सत्र न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा प्रयोग की जा सकती है, क्योंकि न्यायालय में शुरू कार्यवाही, राज्य की राजधानी में जहां उच्च न्यायालय स्थित है, या

मुफस्सिल के किसी न्यायालय में की जानी है । इसलिए उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के बीच क्षेत्राधिकार के टकराव का कोई सवाल नहीं हो सकता। जब उच्च न्यायालय धारा 2 के तहत एक आदेश सुनाता है, उचित मामलों में जहां कार्यवाही राजधानी शहर के किसी भी न्यायालय में शुरू की जानी है, इसे केवल उच्च न्यायालय द्वारा हटाया जा सकता है, जिसमें उच्च न्यायालय स्थित है और अन्यत्र जिला और सत्र न्यायालय के आदेश से हटाया जा सकता है। अधिनियम उच्च न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्रदान करता है और इसके प्रयोग की शर्त के रूप में यह आवश्यक नहीं है कि जिस व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाया जाना है वह अधिकार क्षेत्र से जुड़े न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी क्षेत्र में निवास कर रहा हो या उसका अधिवास हो, न ही आदेश में किसी प्रत्यक्ष क्षेत्रीय कार्रवाई को पारित करने पर विचार किया गया है: यह किसी व्यक्ति के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से जारी किया जाता है और उसे उस संबंध में निर्दिष्ट न्यायालय की अनुमति के बिना कार्यवाही शुरू करने से रोकता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जहां कहीं भी रहता हो या निवास करता हो, उसे धारा 2 के तहत एक आदेश द्वारा रोका जा सकता है।

लेकिन ऐसा कहा जाता है कि विधानमंडल द्वारा धारा 65 में प्रयुक्त व्यापक पदावली के बावजूद 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम 37 की धारा 119 के परिणामस्वरूप कुछ हद तक विसंगतिपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है। यह दावा किया जाता है कि उच्च न्यायालय को किसी मुकदमेबाज

को ऐसी कार्यवाही जो कष्टप्रद है शुरू करने से रोकने की जो शक्ति प्राप्त है उसका प्रयोग पूर्व आंध्र राज्य की सीमा के भीतर अदालतों में शुरू की जाने वाली कार्यवाही या कार्यवाही से उत्पन्न होने वाली कार्यवाही के संबंध में किया जा सकता है। तर्क का निष्कर्ष यह है कि एक वादी को केवल पूर्व के आंध्र राज्य के भीतर जिलों के न्यायालयों में शुरू की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में और उच्च न्यायालय के समक्ष लाई जाने वाली कार्यवाही के संबंध में कष्टप्रद माना जा सकता है। पूर्व आंध्र राज्य के क्षेत्र के भीतर न्यायालयों द्वारा दिए गए आदेशों से अपने अपीलीय, पुनरीक्षण या अधीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में: इसलिए उन जिलों में स्थापित मामलों से उच्च न्यायालय तक पहुंचने वाली कार्यवाही के संबंध में, उसे राज्य के कुछ जिलों में शुरू की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में आगे बढ़ने में असमर्थता का सामना करना पड़ सकता है न कि बाकी के संबंध में। संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 या मूल क्षेत्राधिकार के तहत उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रयोग पर इस तरह के दृष्टिकोण का क्या प्रभाव हो सकता है, उदाहरण के लिए, कंपनी अधिनियम या बैंकिंग कंपनी अधिनियम के तहत, अपीलकर्ता जिसने व्यक्तिगत रूप से अपने मामले पर बहस की है, ने निपटने का प्रयास नहीं किया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 119 प्रदान करती है:

"भाग II के प्रावधानों को उन क्षेत्रों में किसी भी बदलाव के लिए प्रभावी नहीं माना जाएगा, जहां नियत दिन से ठीक पहले लागू कोई भी

कानून विस्तारित होता है या लागू होता है, और मौजूदा राज्य में ऐसे किसी भी कानून में क्षेत्रीय संदर्भ को, जब तक अन्यथा एक सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है, नियत दिन से ठीक पहले उस राज्य के भीतर के क्षेत्रों के रूप में समझा जाएगा।"

उस धारा के अनुसार नियत दिन से पहले लागू कानूनों की क्षेत्रीय सीमा, जब तक कि किसी सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित नहीं की जाती, जारी रहती है। लेकिन धारा 119 को धारा 65(1)(अ) के साथ सामंजस्यपूर्ण ढंग से पढ़ा जाना चाहिए। बाद वाला खंड स्पष्ट शब्दों में घोषित करता है कि मौजूदा आंध्र राज्य के उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र मौजूदा हैदराबाद राज्य से उस राज्य को हस्तांतरित सभी क्षेत्रों तक विस्तारित होगा। यदि यह मान लिया जाए कि आंध्र राज्य के उच्च न्यायालय के पास कष्टप्रद मुकदमेबाजी (रोकथाम) अधिनियम के तहत आदेश पारित करने का अधिकार क्षेत्र है, तो इसे कहना मुश्किल होगा की 1956 के अधिनियम 37 की धारा 119 अभी भी उच्च न्यायालय द्वारा किसी परेशान करने वाले वादी को मुफस्सिल के कुछ क्षेत्रों में, कार्यवाही शुरू करने से रोकने की शक्ति के प्रयोग को प्रतिबंधित करता है और अन्य में नहीं या पूर्व आंध्र राज्य के भीतर के क्षेत्र में अदालतों में शुरू की गई कार्यवाहियों में आदेशों और डिक्री से अपील या संशोधन के माध्यम से कार्यवाही करने से रोकता है, अन्यत्र नहीं। 1953 के अधिनियम 30 द्वारा

संसद ने आंध्र के उच्च न्यायालय को उन सभी क्षेत्राधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार दिया, जो मद्रास के उच्च न्यायालय के पास आंध्र राज्य के क्षेत्रों के भीतर थे और उसके बाद एस द्वारा थे। 1956 के अधिनियम 37 की धारा 65(1)(अ) ने आंध्र प्रदेश के पूरे क्षेत्र पर उस अधिकार के प्रयोग को विस्तार कर दिया, और मेरे फैसले में, इस तर्क को स्वीकार करना असंभव होगा कि कष्टप्रद मुकदमेबाजी (रोकथाम) 1949 के अधिनियम 8 द्वारा प्रदत्त क्षेत्राधिकार के संबंध में, उच्च न्यायालय अपीलकर्ता के विरुद्ध आदेश पारित करने में अक्षम था।

न्यायाधिपति हिदायतुल्ला, ने अधिनियम के प्रावधानों की संवैधानिकता को कायम रखने में जो कहा है, उसमें मुझे कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं उनसे सहमत हूं कि अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने के रूप में असंवैधानिक नहीं है।

हालाँकि, योग्यता के आधार पर, मेरी राय है कि अपीलकर्ता ने विभिन्न न्यायालयों में जो मामले दायर किए थे, वे उसके खिलाफ पारित कठोर प्रकृति के आदेश को उचित नहीं ठहराते थे। अपीलकर्ता का दावा है कि वह हैदराबाद शहर में एक बड़ी संपत्ति का मालिक है, और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है: वह एक व्यापक व्यवसाय भी करता है और अपने व्यवसाय को चलाने और अपनी संपत्ति के प्रबंधन के दौरान,

उसे अक्सर अदालतों का सहारा लेना पड़ता है। अपीलकर्ता का कहना है कि कुछ कारणों से (जिन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है) वह बिना किसी पेशेवर सहायता के अदालतों के समक्ष अपना मुकदमा चलाता है। यह मानते हुए कि अपीलकर्ता ने उन मामलों को स्थापित करने और मुकदमा चलाने में कम निष्पक्षता और अधिक उत्साह दिखाया है जो एक वकील समान मामलों में दिखा सकता है, और उसने जो सोचा था कि कानून में खामियां थीं, उसका लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया था, उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय द्वारा एक व्यापक प्रतिबंध लगाया गया जो उचित प्रतीत नहीं होगा। मैं अपीलकर्ता द्वारा दायर किए गए विभिन्न मामलों की प्रकृति या इस न्यायालय में दायर मामलों की सूची में दिए गए उन मामलों की सामान्य प्रगति और उनमें पारित आदेशों पर ध्यानपूर्वक विचार करने पर सहमत नहीं हो पा रहा हूं कि वे कार्यवाही कष्टप्रद या तुच्छ हैं।

इसलिए मैं अपील की अनुमति देता हूं, लेकिन न्यायाधिपति हिदायतुल्ला द्वारा निर्धारित आधारों पर नहीं।

अपील की अनुमति प्रदान की जाती है।

नोटः- यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुमन मीणा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवाहरिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होना और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।